Consumer Courts Working in the Country

488. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of consumer courts presently working in the country and particularly in the North-Eastern States, State-wise;

(b) whether Government have any proposal to set up more consumer courts particularly in the rural areas of the country; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) At present one National Commission, 32 State Commissions and 526 District Fora have been established in the country, out of which 7 State Commissions and 65 District Fora are in the North-Eastern States. The State-wise information is in the Statement (*see* below).

(b) & (c) The Consumer Protection Act, 1986 provides for setting up of additional District Forum in a district if so warranted by the work-load. The responsibility for setting up of additional District Forum and its location rests with the State Government/UT Administrations.

Statement

State-wise Details of the Consumer Courts

States/UTs	No. of State Commission	No. of District Forum
Andhra Pradesh	1	25
Arunachal Pradesh	1	13
Assam	1	23
Bihar	1	55
Goa	1	2
Gujarat	1	20
Haryana	1	17
Himachal Pradesh	1	12
Jammu & Kashmir	1	2
Karnataka	1	22
Kerala	1	14
Madhya Pradesh	1	45
Maharashtra	1	34
Manipur	1	8
Meghalaya	1	7
Mizoram	1	3
Nagaland	1	8
Orissa	1	31
Punjab	1	17
Rajasthan	1	33
Sikkim	1	4
Tamil Nadu	1	24
Tripura	1	3
Uttar Pradesh	1	72
West Bengal	1	19
A&N Island	1	2
Chandigarh Admn.	1	2
D&N Haveli	1	1
Daman & Diu	1	2
Delhi	1	4
Lakshadweep	1	1
Pondicherry	1	1
TOTAL	32	526

Review of Functioning of TPDS

489. DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the functioning of the newly Targeted Public Distribution System introduced earlier this year;

(b) if so, the assessment regarding the States of Bihar, Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan;

(c) whether additional measures are being contemplated to streamline the system; and

(d) if so, the details thereof and what are the financial implications?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The States of Bihar, Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan have made necessary arrangements like identification of Below Poverty Line (BPL) families and issue of special cards, constitution of Vigilance Committees etc. and implemented TPDS w.e.f. 1.6.1997.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल और गेहूं के आवंटन पर प्रतिबंध लगाया जाना

490. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल और गेहूं के संबंध में आमतौर पर किए जाने वाले आवंटन पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कटौती के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई योजना उत्तरदायी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या खाद्यान्नों के कोटे में वृद्धि करने हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी हां।

(च) आवंटन बढ़ाने से संबंधित अनुरोध की जानकारी देने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(छ) सरकार ने अनुपत्र में दिए गए विवरण के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आवंटन किया है। **(देखिये परिशिष्ट 182, अनुपत्र सं० 8)**

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त आवंटन की मांग

क्रम सं०	पत्र संख्या और तारीख	राज्य का नाम	अनुरोध का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	एफ०एस०बी० 256/97/3, दिनांक 20.3.1997	असम	बाढ़ राहत के लिए अतिरिक्त 20,000 टन चावल। जिसकी उठान की वैधता 31 अक्तूबर, 1997 तक है।
2.	शून्य दिनांक 23.7.1997	बिहार	बाढ़ राहत के लिए जून के कोटे का प्रयोग न किया गया भाग जारी करना।
3.		दिल्ली	मई, 97 के आवंटन को बनाए रखने के लिए जून, 97 से 24,600 टन चावल और 7110 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
4.	सचिव (खाद्य और नागरिक पूर्ति) से नोट दिनांक 14.8.1997	गोवा	2500 टन चावल और 100 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
5.	अ०स० पत्र संख्या ए०एन०जे०/रेजमट० /124/94-95, दिनांक 30.7.1997	गुजरात	चावल और गेहूं की अतिरिक्त मात्रा।
6.	(1) एफ०जी०—3-97/6322 दिनांक 14.7.1997	हरियाणा	सरकारी विभाग के लिए 200 टन गेहूं के आवंटन के लिए अनुरोध।
	(2) एफ०जी०-3-97/33/आर०ए० दिनांक 8.5.97	हरियाणा	चावल और गेहूं की अतिरिक्त मांग।
7.	(1) सी०एम०एस०—97-एफ०एस०टी०-एन०डी० दिनांक 5.5.1997	जम्मू व कश्मीर	वार्षिक 1,88,000 टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन